Tirupati Balaji Group / Established 2009 / Ghaziabad
R.N.I No. UPBIL/2009/28691, DAVP Code: 101473

Page 8 / Price Rs. 2.00 / Ghaziabad, Sunday, 26 May 2019
Postal Registration No. UP/GBZ-80/2016-18

TIRUPATI BALAJI CHRONICLE

Vol./Year-10 Issue - 51

Hindi / English (Bi-Lingual) Weekly Ghaziabad
केन्द्र एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त

www.tbcgzb.com

आने वाले समय में देश में सभी तरह की एलोपैथिक दवाओं की कीमतें मूल्य नियंत्रण के दायरे में आ सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दवाओं पर 30 प्रतिशत से ज्यादा का मुनाफा नहीं वसूला जाएगा।

Inside Ghaziabad

पेज नंबर 2
आइएमटी की 10,841 भूमि का आवंटन निरस्त, टूटेगा हॉस्टल

पेज नंबर 5
Ghaziabad boy battles storms, scales Mt Everest

TIRUPATIEYE

नोएडा यूनियन बैंक घोटाले में हुई गवाही

गाजियाबाद : नोएडा के यूनियन बैंक लोन घोटाले में सीबीआइ कोर्ट में सुनवाई हुई। मंगलवार को सुनवाई के दौरान बैंक के रिटायर्ड मुख्य महाप्रबंधक आरबी बागड़ी की गवाही हुई। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख लगा दी। बता दें कि नोएडा में यूनियन बैंक की शाखा से दिल्ली की पृथ्वीराज जूलर्स कंपनी के प्रोपराइटर राजकुमार सामंता ने बैंक मैनेजर मनोज श्रीवास्तव से फर्जी कागजों के आधार पर वर्ष 2008 में 40 लाख रुपए का लोन स्वीकृत कराया था।

अक्टूबर तक बांटे जाएंगे कृत्रिम उपकरण

गाजियाबाद : दिव्यांग सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत चल रहे कृत्रिम व सहायक उपकरण वितरण का काम अक्टूबर तक खत्म करना है। इस वित्तीय वर्ष में जितना लक्ष्य मिलता है, उसे हर हाल में पूरा करना होगा। अपर मुख्य सचिव महेश चंद्र गुप्ता की ओर से जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि दिव्यांगों को बांटे जाने वाले कृत्रिम व सहायक उपकरणों के वित्तीय वर्ष 2019–20 के लक्ष्य को अक्टूबर 19 तक पूरा करना है।

गोशालाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी

गाजियाबाद : जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से जिले में बन रही गोशालाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डॉ. विजेंद्र त्यागी ने बताया कि जिले में पांच गोशालाएं निर्माणाधीन हैं। जिनके निर्माण का कार्य जुलाई माह तक पूरा हो जाएगा। वहीं मुरादनगर में बन रही वृद्ध गोशाला केंद्र भी लगभग तैयार है।

रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर ने निशुल्क बांटी 500 नेपकिन

नोएडा के अनाथालयों, झुग्गी झोपड़ी व स्कूलों में निशुल्क की गई वितरित

नोएडा : महावारी स्वच्छता दिवस पर मंगलवार को रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर ने नोएडा के कई अनाथालयों, झुग्गी–झोपड़ी व स्कूलों में निशुल्क 500 सेनेटरी नेपकिन का वितरण किया। रोटरी क्लब ऑफ इंदिरापुरम गैलोर के चार्टर प्रेजीडेंट डा.धीरज कुमार भार्गव ने कहा कि झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाली महिलाएं व लड़कियां महावारी के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती है जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। जिसे धोकर और छुपाकर सुखाने के चक्कर में खुली हवा व धूप तक नहीं लगने देती हैं, साथ ही बार–बार इसी का इस्तेमाल करती रहती हैं, जो कि गंभीर इंफेक्शन को न्योता देता है। वहीं क्लब की पूर्व अध्यक्ष मनीषा भार्गव ने झुग्गी झोपड़ी व अनाथालयों में रहने वाली महिलाओं व युवतियों को महावारी के दौरान सेनेटरी नेपकिन का इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अधिक बहाव में बार–बार नेपकिन बदलने के झंझट से बचने के लिए कई महिलाएं एक ही बार में 2 नेपकिन लगा लेती हैं। यह तरीका बिल्कुल गलत है। एक नेपकिन की जितनी सोखने की क्षमता है वह उतना ही सोखेगा और 2 नेपकिन एक साथ लगाने से बैक्टीरिया अधिक पनपेंगे और ये सिर्फ दुर्गंध को न्योता देंगे। साथ ही आपको असुविधा भी होगी।

घर का सपना होगा पूरा, पीएम आवास प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार

गाजियाबाद : आम चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के एजेंडा में शामिल 2022 तक सबको घर देने के वायदे को पूरा करने में जुटेगी। अकेले गाजियाबाद में जीडीए को 2022 तक 36 हजार पीएम आवास के निर्माण का टारगेट दिया गया है। इनमें पहले चरण में प्राधिकरण ने 18 हजार पीएम आवास में से 11887 पीएम आवास की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं बाकी प्रोजेक्ट की शासन व केंद्र में लटकी डीपीआर की बाधा के हटने की संभावना अब प्रबल हो गई है। सबको सस्ते घर मुहैया की योजना पर केंद्र सरकार के तेजी से बढ़ने से लोगों को जल्द घर मिलने का सपना पूरा हो सकेगा। दूसरी ओर बीते पांच साल में मोदी सरकार के रुख को देखने हुए रियल एस्टेट में फिर से बूम आने की संभावनाओं पर संशय छाने लगा है। रियल एस्टेट क्षेत्र में वर्तमान में बिल्डर्स को अपने प्रोजेक्ट में खाली पड़े घरों को बेचने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे में फिर से मोदी सरकार आने से पहले पीएम आवास प्रोजेक्ट में दिलचस्पी नहीं दिखाने वाले बिल्डरों के आगे आने की पूरी संभावना है। वर्तमान में महानगर में जीडीए की ओर से केवल मधुबन बापूधाम योजना में 856 पीएम आवास के निर्माण का काम तेज गति से किया जा रहा है। यहां सर्वाधिक भवनों का निर्माण होना है।

Safety check in Ghaziabad shows most don't have NOCs

GZB: The Ghaziabad fire department has launched a safety audit of educational institutes in the city in the aftermath of the blaze at a coaching institute in Surat in which 19 students were killed. On Saturday, a police team conducted surprise inspections at private coaching centres in Ghaziabad to check for violations, if any. "Till date, we have not issued any NOC to any coaching centre that is operating in the city," said Sunil Singh, chief fire officer. "We have asked for a complete list of registered coaching centres from the administration and accordingly, we will be issuing notices to such erring institutes," he added. According to rules, a fire NOC is not required in a building that is spread over an area of less than 500sqm and has a height of less than 15 metres. "But there are many institutes that are openly flouting fire safety norms. We will serve notices to them action and action will be initiated against the owners," said Singh. In May 2016, a major fire had broken out in an Indiamart building in Raj Nagar, claiming six lives. In the investigation, it had been revealed that fire safety norms were followed in the building and the owners had not taken NOC from the fire department.

किसान सम्मान निधि में छूटे किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू

गाजियाबाद : किसान सम्मान निधि के तहत छूटे हुए किसानों को एक बार फिर मौके मिलने जा रहा है। किसान सम्मान निधि के तहत लाभ से पाने से वंचित रह गए योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेखपाल से प्रमाण पत्र लेकर उन्हें संबंधित कृषि प्रसार अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। कृषि विभाग ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरु कर दी है। जिला कृषि अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना के तहत दो हेक्टेयर या उससे कम भूमि वाले किसानों को शासन की ओर से साल में छह हजार रुपये दिए जाते हैं। जो कि दो–दो हजार तीन किस्तों में मिलने हैं। योजना के तहत जिले में करीब 32 हजार किसानों को पहली दो किस्तों मिल चुकी हैं। इन किसानों के अलावा अभी भी बहुत से किसान बचे हुए हैं। जो पहले फेज में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए थे। जिले में ऐसे किसानों की संख्या करीब 5 हजार है। इन्हें रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया गया है। ऐसे किसान परिवार जिनके पास कृषि भूमि दो हेक्टेयर या उससे कम है, वह योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए पहले लेखपाल से पात्रता पूर्ण प्रमाण पत्र लेना होगा।

तुलसी निकेतन में बनेंगे 15 मंजिले टावर

गाजियाबाद : जीडीए ने तुलसी निकेतन के पुनर्निर्माण का प्लान तैयार कर लिया है। चार हेक्टेयर भूमि पर दो चरणों में पंद्रह मंजिल के आठ ब्लॉक बनाए जाएंगे। उसमें तुलसी निकेतन में रहने वालों को शिफ्ट करने के बाद पुराने फ्लैट ध्वस्त कर बाकी चार हजार हेक्टेयर जमीन को खाली किया जाएगा। उस पर दो से चार बीएचके के फ्लैट बनाकर बेचे जाएंगे, ताकि पुनर्निर्माण की लागत वसूली जा सके। यह जमीन बिल्डर को बेचकर लागत वसूलने पर भी मंथन चल रहा है। आठ हेक्टेयर में वर्ष 1990 में तुलसी निकेतन को बसाया गया था। इसमें 2292 ईडब्ल्यूएस और एलआइजी फ्लैट

बनाए गए थे। अब इन फ्लैटों की हालात जर्जर हो चुकी है। दो बार छत गिरने से हादसा हो चुका है। अनहोनी की आशंका को खत्म करने के लिए जीडीए ने पुनर्निर्माण की योजना बनाई है। पहले पार्क और कॉमर्शियल एरिया को ध्वस्त कर वहां पहले चरण में पंद्रह मंजिल के टॉवर में 692 फ्लैट बनाए जाएंगे। इनमें लोगों को शिफ्ट करने के बाद दूसरे चरण में 1200 फ्लैट बनाए जाएंगे। उनमें बाकी लोगों को शिफ्ट करने दिया जाएगा। जिनकी दुकानें हैं, उनके लिए दुकान भी बनाई जाएंगी। जीडीए अधिकारियों ने बताया कि ओपन स्पेस उतना ही छोड़ा जाएगा, जितना अभी है। इतना कार्य होने के बाद पुराने फ्लैट ध्वस्त कर जमीन को खाली किया जाएगा। करीब चार हेक्टेयर जमीन खाली होगी। उस पर दो, तीन और चार बीएचके के 900 से 1200 फ्लैट की ग्रुप हाउसिंग विकसित की जाएंगी। यह तय होना बाकी है कि ग्रुप हाउसिंग जीडीए बनाएगा या बिल्डर को इसके लिए जमीन बेची जाएगी। केवल पुनर्निर्माण की लागत वसूलने के लिए ऐसा किया जाएगा। ताकि, जीडीए पर आर्थिक बोझ न बढ़े।

प्रतिदिन एनएचएम की समीक्षा करेंगे सीएमओ

गाजियाबाद : मुख्य चिकित्साधिकारी डा. एनके गुप्ता अब रोजाना नेशनल हेल्थ मिशन की समीक्षा करेंगे। इस संबंध में उन्होंने सोमवार को नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के नोडल अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सीएमओ ने कहा है कि सभी नोडल अधिकारी रोजाना शाम चार बजे तक मिशन के संबंध में रिपोर्ट करेंगे। बता दें कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के नोडल अधिकारी एसीएमओ डा. संजय अग्रवाल हैं और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के नोडल अधिकारी डा. डीएम सक्सेना हैं। सीएमओ ने यह निर्देश विकास भवन सभागार में सोमवार को राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, डा. महेन्द्र सिह द्वारा ली गई बैठक के बाद दिए।

यमुना को प्रदूषित करने वाली 20 इकाइयों पर लगेगा 50 लाख जुर्माना

गाजियाबाद : औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले दूषित जल से प्रदूषित होती यमुना को बचाने के लिए पानी के नमूने लिए गए, जिनमें 20 इकाइयों के नमूने फेल हो गए। दूषित जल इंदिरापुरी लोनी व साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र के नाले से यमुना में प्रवाहित हो रहा था। इन सभी इकाइयों के खिलाफ क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 50–50 लाख रुपये के जुर्माने की संस्तुति लखनऊ मुख्यालय को भेज दी गई है। इसके साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यमुना नदी को प्रदूषित करने वाली औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ एनजीटी की सख्ती पर प्रदूषण विभाग, नगर निगम, यूपीएसआइडीसी,

उद्योग केंद्र व विद्युत विभाग सक्रिय हुए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नेतृत्व में औद्योगिक क्षेत्रों में 312 इकाइयों का सर्वे कर निकलने वाले पानी की जांच की गई, जिसमें 20 औद्योगिक इकाइयों के जल के नमूने फेल हो गए। इन उद्योगों में कई जगह ईटीपी प्लांट तो लगे थे, लेकिन वह चालू नहीं मिले। इकाइयों में लगे ईटीपी प्लांट को स्पेशल कर्मी के बजाए औद्योगिक इकाईयों के कर्मचारी ही संचालित करते हुए मिले। पानी के नमूने फेल होने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इन सभी 20 औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ मुख्यालय को अपनी रिपोर्ट और इनके खिलाफ 50–50 लाख रुपये का जुर्माने की संस्तुति करने के साथ ही उक्त उद्योगों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। ये हैं 20 इकाइयां : मै. अनुराधा फैब्रिकेटर्स, मै. कैपिटल प्रा. लि. (प्राइम होंडा), मै. कैपिटल कार्स प्रा. लि. (प्राइम होंडा), मै. डाबर इंडिया लि., मै. फैब केयर, मै. फेयर डील कार्स लि., मै. जीएस दास अपेरल प्रा. लि., मै. गोयल प्रोसेसर्स, मै. हरप्रीत फोर्ड मोटर्स प्रा. लि., मै. केएम प्रोसेसर्स, मै. केएम प्रोसेसर्स, मै. कृष्णा ड्क्षप्रटर्स प्रा. लि., मै. महावीर इंटरप्राइजेज, मै. रचना मैटल इंडस्ट्रीज प्रा. लि., मै. रिजेंसी साईकल प्रा. लि., मै. एसबीएल लि., मै. सिंघला एग्रोयर्स प्रा. लि. , मै. सोना इंडस्ट्रीज, मै. स्पार्क इंजीनियरिंग प्रा. लि., मै. स्पेसिलिटी टूल्स प्रा. लि. शामिल हैं। उक्त इकाइयां अधिकांश औद्योगिक क्षेत्र साइट–4 साहिबाबाद की हैं।

जून में होगी जीडीए की बोर्ड बैठक

गाजियाबाद : जीडीए बोर्ड की बैठक जून में होगी। जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने बताया कि बैठक की तारीख तय करने के लिए प्रस्ताव कमिश्नर को भेज दिया गया है। उसमें मधुबन–बापूधाम में जीडीए के नए भवन का निर्माण, तुलसी निकेतन योजना का पुनर्निर्माण, वेयर हाउसिंग व लॉजिस्टिक की विशेष नीति, मधुबन–बापूधाम योजना के तलपट मानचित्र में बदलाव, सैट बैक का निर्धारण, हाईटेक व इंटीग्रेटिड योजनाओं की प्रगाति, नेहरू स्टेडियम की लीज, कर्पूरी पूरम में स्टाफ क्वार्टर विक्रय करने, पीएम आवास योजना में अधिभार को अन्य योजना पर भारित करने, खेल कूद मैदानों के लिए आवंटित भूमि की दरें निर्धारित करने समेत कई प्रस्ताव रखे जाएंगे। मधुबन–बापूधाम योजना में शमशान घाट के पास कई आवासीय प्लॉट आवंटित कर दिए गए थे। साथ ही पास में ग्रुप हाउङ्क्षसग प्रस्तावित की गई थी। जिन लोगों को प्लॉट आवंटित हो चुके हैं, उन्होंने आपत्ति जताई थी कि शमशान घाट के पास रहना मुमकिन नहीं। आवंटी दूसरी जगह प्लॉट देने की मांग कर रहे थे। इस मांग को वाजिब मानते हुए लेआउट में आंशिक बदलाव करने का निर्णय हुआ है। नए लेआउट में शमशान घाट के पास पार्क बनाया जाएगा। पार्क की जगह प्लॉटिंग की जाएगी। ग्रुप हाउसिंग की लोकेशन भी बदलेगी। योजना के बीच से विद्युत हाईटेंशन लाइन जा रही है। पुराने लेआउट में इसके आसपास आवासीय भूखंड दर्शाए गए हैं।

एलईडी लाइट लगाने वाली कंपनी का भुगतान स्वीकृत

गाजियाबाद : नगर निगम में व्हाइट प्लाकार्ड कंपनी को एलईडी लाइटों का भुगतान करने का रास्ता साफ हो गया। मेयर आशा शर्मा ने बोर्ड की प्रत्याशा में पौने चार करोड़ रुपये के भुगतान को स्वीकृति प्रदान कर दी है। शासन ने निगम को कंपनी का जून 2018 से अप्रैल 2019 तक का भुगतान जारी करने का आदेश दिया था। कंपनी ने दावा किया है कि उन्होंने 48 हजार सोडियम लाइट हटाकर उनकी जगह स्ट्रीट पोल पर एलईडी लाइटें लगाई हैं। उससे 85 लाख रुपये बिजली का बिल हर महीने कम हुआ है। जबकि, निगम अधिकारियों की जांच में पाया गया कि 54 लाख रुपये का बिजली बिल कम हुआ है।

नगर निगम ने नालों के किनारे नहीं लगाई ग्रिल, मिली फटकार

गाजियाबाद : नालों के किनारे लोहे ही ग्रिल लगाने के शासन के आदेश को दरकिनार करने पर नगर निगम अधिकारियों को फटकार पड़ी। आबकारी, वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी ने सोमवार को निरीक्षण में नाले के किनारे ग्रिल न लगी होने पर नाराजगी जताई। निर्देश दिया कि जल्द ग्रिल लगवाई जाएं। ऐसा होने पर कोई नालों में नहीं गिरेगा। साथ ही नालों में कूड़ा पहुंचने से रोका जा सकेगा। प्रमुख सचिव ने साईं उपवन में पूजन सामग्री से कंपोस्ट बनाने वाले प्लांट का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया गया कि इस प्लांट में शहर के सौ से ज्यादा धार्मिक स्थलों से पूजन सामग्री लाई जाती है। इससे बनी कंपोस्ट को पेड़ों में डाल कर उन्हें हरा–भरा किया जाता है। वहीं लीफ कंपोस्टिंग प्रणाली का निरीक्षण किया। देखा कि पेड़ों से गिरे पत्तों को जाली के घेरे में इकटठा किया जाता है। उससे हवा क्रॉस कराकर पत्तों की खाद बनाई जा रही है। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि पत्तों से बनी खाद को सबसे अच्छा माना जाता है। मोहननगर में तरल खाद का प्लांट दिखाया गया। निगम अधिकारियों के इस प्रयास कि प्रमुख सचिव ने सराहना की। राजनगर एक्सटेंशन के पास नंदी पार्क का निरीक्षण भी किया। वहां सफाई व्यवस्था दुरुस्त मिली।

आइएमटी की 10,841 वर्गमीटर भूमि का आवंटन निरस्त, टूटेगा हॉस्टल

गाजियाबाद : देश के नामी प्रबंधन संस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (आइएमटी) की 10,841 वर्ग मीटर जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। जीडीए वीसी कंचन वर्मा ने सचिव की अध्यक्षता वाली जांच समिति के फैसले पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही प्रवर्तन अनुभाग को जमीन का कब्जा वापस लेने और उस पर बने हॉस्टल को तोडने का निर्देश दे दिया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे बकुल नाथ इस संस्थान के प्रेसिडेंट हैं। भाजपा पार्षद राजेंद्र त्यागी ने राजनगर सेक्टर–20 में आइएमटी परिसर के अंदर जमीन पर अवैध कब्जा होने का आरोप लगाया था। राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत में बताया था कि वर्ष 1968 में गाजियाबाद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट (अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण) ने लाजपत राय कॉलेज के लिए यहां 54049.25 वर्ग गज भूमि लाजपतराय स्मारक महाविद्यालय सोसायटी को आवंटित की गई थी। आवंटन के वक्त बीच में 10841 वर्ग मीटर जमीन के एक टुकड़े पर विवाद चल रहा था। उस पर कोर्ट से स्टे था। वर्ष 1977 में स्टे खारिज हो गया। इस भूमि पर गलत तरीके से आइएमटी का निर्माण कर दिया गया।

ऑपरेशन क्लीनअप से कसा जाएगा बिजली चोरों पर शिकंजा

गाजियाबाद : पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम एक जून से ऑपरेशन क्लीनअप चलाकर बिजली चोरों के खिलाफ अभियान चलाएगा। इस अभियान को विद्युत विभाग ग्रामीण क्षेत्र में चलाएगा। इसके लिए गांव में चोरी से बिजली का इस्तेमाल कर रहे लोगों के खिलाफ कार्यवाही होगी। विद्युत विभाग तमाम प्रयासों के बावजूद लाइनलोस को लेकर परेशान है। ग्रामीण इलाकों में बड़े पैमाने पर हो रही विद्युत चोरी को रोकने के लिए विभाग ने ऑपरेशन क्लीन अप अभियान शुरू करने की तैयारी की है, जो एक जून से आरंभ किया जाएगा।

प्रताप विहार में सितंबर से चालू होगा 220 एमवी बिजलीघर

गाजियाबाद : प्रताप विहार में विद्युत निगम ट्रांसमिशन बिजलीघर बनाने का कार्य कर रहा है। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने निर्माणाधीन बिजलीघर हाईटेक होगा। सितंबर में इसे चालू कर दिया जाएगा। एक्सईएन ट्रांसमिशन विकास गुप्ता ने बताया कि इसमें हाईब्रिड फीडर, तार आदि का उपयोग होगा। बिजली कटने या फाल्ट होने की स्थिति में अलार्म बज उठेंगे। ताकि अधिकारी सतर्क होकर तत्काल फाल्ट पर ध्यान देकर आपूर्ति सुचारू करा सकें। इस बिजलीघर से टीएचए क्षेत्र को भी बड़ा फायदा मिलेगा। अगर टीएचए के साहिबाबाद 220 एमवी और इंदिरापुरम के 400 एमवी उपकेंद्र में कोई कटौती या फॉल्ट होता है तो इसी बिजलीघर से उन इलाके में सप्लाई दी जाएगी। वहीं, उपकेंद्र से प्रताप विहार, विजयनगर और खासतौर से सिद्धार्थ विहार आवास विकास योजना में रहने वाले करीब छह लाख लोगों के साथ–साथ औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों को भी फायदा मिलेगा।

संपत्ति नाम परिवर्तन शुल्क वसूलना कोर्ट के आदेश की अवहेलना

गाजियाबाद : प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य एवं निगम पार्षद हिमांशु मित्तल ने प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव को पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा कि शासन ने अपने आदेश में नामांत्रण शुल्क के बारे में लिखा कि स्टांप शुल्क जिस मूल्य के साथ एक प्रतिशत नाम परिवर्तन शुल्क भी लिया जाएगा, जो न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। इस बारे में उश्चतम न्यायालय एसएलपी संख्या 16570ध्2018 मुरादाबाद डवलपमेंट अथॉरिटी बनाम महेश चंद्र अग्रवाल एंड ब्रदर्स अपना फैसला सुना चुका है। इसी याचिका में बीरेंद्र कुमार बनाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में अपना निर्णय दे चुका है। बावजूद इसके नाम परिवर्तन शुल्क लगातार लिया जा रहा है।

प्रशिक्षित पुलिसकर्मी संभालेंगे हिंडन टर्मिनल की सुरक्षा

गाजियाबाद : हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल की सुरक्षा स्थानीय पुलिसकर्मियों के जिम्मे होगी। इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। एसएसपी उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया कि रेंज भर से 70 पुलिसकर्मियों को टर्मिनल की सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है। साहिबाबाद के सर्किल आफिसर को टर्मिनल का मुख्य सुरक्षा अधिकारी(सीएसओ) बनाया गया है। टर्मिनल की सुरक्षा द्विस्तरीय होगी, जिसे आउटर कार्डन और इनर कार्डन में बांटा गया है। बता दें कि 15 जून से गाजियाबाद के इस टर्मिनल से आठ शहरों के लिए घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो जाएगी। आचार संहिता खत्म होते ही एयरपोर्ट से 15 जून से उड़ानें शुरू करने का फैसला लिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी

ऑफ इंडिया के अलावा इंडिगो व विस्तारा एयरलाइंस के अधिकारी यहां निरीक्षण कर चुके हैं। इस टर्मिनल की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा जनपद पुलिस को दिया गया है। एसएसपी ने बताया कि गाजियाबाद के अलावा नोएडा व मेरठ समेत रेंज के सभी जिलों से पुलिसकर्मी चुने गए हैं। कुल 70 पुलिसकर्मी चयनित हुए हैं। इनमें से 50 को एक हफ्ते का विशेष प्रशिक्षण दे दिया गया है। एजेंसी द्वारा एयरपोर्ट की सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं के बारे में पुलिसकर्मियों को बताया गया है।

इन शहरों के लिए मिलेगी उड़ान

उत्तर प्रदेश के अयोध्या, उत्तराखंड के पिथौरागढ़, गुजरात के जामनगर, हिमाचल के शिमला, महाराष्ट्र के नासिक, कर्नाटक के हुबली, गुलबर्गा और केरल के कन्नूर के लिए यहां से शुरुआत में उड़ान मिल सकेंगी। हालांकि कुछ समय तक सफल संचालन के बाद गोरखपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, लखनऊ आदि रूटों पर भी उड़ान शुरू की जाएंगीं। एयरपोर्ट के शुरू होने के बाद धीरे–धीरे एयरलाइंस अपनी फ्लाइट इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिंडन एयरपोर्ट टर्मिनल पर शिफ्ट करेंगी।

गुरुग्राम में होगा मेट्रो का विस्तार, यहां बनेंगे 25 नए मेट्रो स्टेशन

गुरुग्राम : मिलेनियम सिटी में मेट्रो विस्तार पर सोमवार को अंतिम मुहर लग गई। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) की चौथी बैठक में मेट्रो की डीपीआर मंजूर कर दी गई। शहर को जाममुक्त बनाने के लिए हुडा सिटी सेंटर से मेट्रो का विस्तार करके इसे रैपिड मेट्रो के साइबर सिटी स्टेशन से जोड़ा जाएगा। मेट्रो रेल लाइन की कुल लंबाई 31.11 किलोमीटर है। इसमें 25 स्टेशन होंगे, जिसमें छह इंटरचेंज स्टेशन होंगे। इस मेट्रो लाइन के निर्माण पर अनुमानित लागत 5126 करोड़ रुपये होगी और इसके वर्ष 2023 में चालू किए जाने की संभावना है।

दो जून को 45 सेंटरों पर होगी सिविल सेवा परीक्षा, 22622 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे

गाजियाबाद : दो जून को होने वाली सिविल सेवा की परीक्षा को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिले में सिविल सेवा की परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित कराई जाएंगी। जिले में 45 सेंटरों पर होने वाली परीक्षा को लेकर प्रशासन ने खाका तैयार कर लिया है। इसके लिए प्रत्येक सेंटर पर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी के साथ पुलिसबल की तैनाती की जाएगी। दो जून रविवार को आयोजित होने वाली परीक्षा में 22622 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। यह परीक्षा दो पालियों में सुबह साढ़े नौ बजे से दोपहर साढ़े 12 बजे और दोपहर साढ़े चार बजे से लेकर शाम साढ़े चार बजे तक कराई जाएंगी। जीटी रोड स्थित शंभू दयाल इंटर कॉलेज को दिव्यांगों का सेंटर बनाया जा रहा है। यहां अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्था कराई जाएगी। उनके लिए सेंटर पर व्हील चेयर की व्यवस्था रहेगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास कड़ी निगरानी रखी जाएगी और साथ ही कड़ी चेकिंग के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। एडीएम वित्त सुनील कुमार सिंह ने बताया कि दो जून को होने वाली परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली हैं। जिले के 45 केंद्रों पर परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। इस परीक्षा में जिले में 22622 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे।

विवेचक समेत कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ अर्जी स्वीकार

गाजियाबाद : ट्रॉनिका सिटी थाने की हवालात में महिला की मौत के मामले में विवेचक समेत कई पुलिस कर्मियों के खिलाफ दाखिल अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अधिवक्ता खालिद खान ने बताया कि उन्होंने अपनी मुवक्किल मेनका त्यागी निवासी नौरसपुर की ओर से 15 नवंबर 2018 को कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। मेनका का कहना है कि 13 मई 2018 को ट्रॉनिका सिटी एसएचओ श्यामवीर सिंह, दरोगा जितेंद्र चौहान, ललित, राजेश्वर और सन्नी व अन्य पुलिसकर्मी उसकी मां सरिता त्यागी को एक हत्या के मामले में पूछताछ के लिए थाने ले गए थे। आरोप है कि पुलिस ने सरिता को हवालात में बंद कर मारपीट की थी, जिससे उसकी कॉलर बोन व पसली टूट गई। वहीं, जब उसने पीने के लिए पानी मांगा था तो पुलिस ने उसे पानी नहीं पिलाया था। मेनका का आरोप है कि पुलिस ने सरिता त्यागी के हाथ पैर बांधकर उसे जहरीला पदार्थ पिलाया था, जिससे अगले दिन 14 मई को सरिता त्यागी की थाने में ही मौत हो गई थी। वहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत कारण कॉलर बोन व तीसरी पसली में फैक्चर और खून जमा होना पाया गया था। इसके अलावा बिसरा रिपोर्ट में पेट, आंत, लीवर, किडनी व ब्लड में जहर होना पाया गया था। इस मामले में ट्रॉनिका सिटी थाने के इंस्पेक्टर रहे नीरज कुमार सिंह ने मामले की जांच की और जांच के मात्र 23 दिन बाद आरोपी इंस्पेक्टर श्यामवीर सिंह को क्लीन चीट देते हुए कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। आरोप है कि इस मामले में आईओ नीरज कुमार ने पीडिता और गवाहों के असत्य व अपूर्ण बयान कोर्ट में दे दिए। इसके अलावा उन्होंने पुलिसकर्मियों को लाभ पहुंचाने के लिए सीएचसी लोनी के डॉक्टर के फर्जी बयान भी केस डायरी का हिस्सा बनाए। वहीं केस डायरी में लिखा कि मृतका को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जबकि उन्होंने उसे एसीजेएम–5 की कोर्ट में पेश किया था। इसके अलावा विवेचक ने यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन करते हुए केस डायरी के बीच में 12 पेज फाड़ दिए, जिसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य लिखे थे।

EDITORIAL

'After Sabka Saath, Sabka Vikas, win Sabka Vishwas': Modi's message of inclusion

At the parliamentary party meeting of the National Democratic Alliance (NDA) on Saturday, Prime Minister-elect Narendra Modi gave one of his most significant speeches in recent times. He was addressing multiple constituencies – members of Parliament (MPs) of the Bharatiya Janata Party (BJP) and MPs belonging to allies, BJP workers on the ground, his larger ideological fraternity of the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), including its more belligerent affiliates, and the country at large. By focusing on inclusion, restraint, the importance of coalitions and regional aspirations, commitment to constitutional values, and the path ahead, Mr Modi has laid out the roadmap for the next five years.The first important intervention was with regard to minorities. Mr Modi pointed out that he had, in 2014, said that his government would work for the poor, did so, and was rewarded in the polls, for it is the poor that elected the government back. There was a multi-class coalition that propelled the BJP to a majority, but it is true that there has been a broadening of the party's class base with the rural poor contributing to the saffron surge. This time, he said the government would continue to focus on the poor - but also the minorities who had been "deceived" so far - who had been made to live in fear and treated as mere vote bank. It was time to end the trust deficit with them, Mr Modi declared, and added "Sabka Vishwas" to his slogan of "Sabka saath, sabka vikaas". He also pointed out to his MPs that they must work for all, not merely those who voted for them. This is admirable messaging. While the BJP would do well to introspect how its own ideological world view and actions on the ground have contributed to insecurity among minorities, if indeed Mr Modi lives up to his word, and his government is non-discriminatory in letter and spirit, it will mark a significant departure in the relationship between the regime and the country's substantial minorities.

Mr Modi's emphasis on restraint in speech is also noteworthy. It is through statements that a segment of BJP leaders created a climate of intolerance, anger, even hate over the past five years. By warning them to be careful, and not create problems, Mr Modi was not just seeking to avoid future controversies but also perhaps disassociating himself from any such rhetoric that may emanate from the party ranks. And by reaching out to his allies, even though the BJP on its own has a majority, he presented a politically inclusive image, laced with statesmanship. If you add together Mr Modi's first tweet, which mentioned an inclusive India, his victory speech where he emphasised the need to take the opposition along, his gesture of paying his respects to party veterans LK Advani and Murli Manohar Joshi, and his speech on Saturday, it appears that the PM in this term is seeking to be a truly unifying figure. And this is coming from a position of supreme strength and confidence. His challenge is in operationalising all of this into action on the ground now.

-By Dr. Dheeraj Kumar Bhargava

The challenges ahead for Britain's next PM

The ruling Conservative Party has begun the process of choosing a new prime minister for Britain following Theresa May's announcement that she will resign her office on June 7. The next prime minister will face the same political minefield that May was unable to navigate. There will be three main sources of danger. One is bridging the gaps within the Conservatives about what sort of Brexit will Britain carry out. This division, and the seeming impossible task of finding a middle path between hardline "no deal Brexiteers" and those who want some sort of soft economic union, has been the primary reason the May prime ministership failed. Two is ensuring that any such resolution will not drive large

numbers of voters into the hands of the new right-wing Brexit party or towards the liberal-left opposition. Finally, to then sell any Brexit deal to the European Union and, preferably, find means to smoothen the sharper economic consequences of a clean break. Outsiders have watched with a mix of awe and embarrassment at how Ms May has stoically stumbled from one Brexit humiliation to another over the past two years. When her cabinet mutinied, she accepted her time was up. The problem is Britain is no closer to a viable Brexit plan than before. The Conservatives now seem set to choose a hardline Brexiteer as the next prime minister. If so, this will bring Britain the closest it has been so far to a full break with the EU, without any sort of economic union. This will deliver a sharp economic cost to Britain, driving its economy into recession and making it far less attractive as an investment site for Indian and other foreign investors. Since it is assumed this will not be palatable to any prime minister, a new round of intra-party squabbling can be expected. But the Brexit debate has lurched strongly to the right with May's announcement. Divorce, without visitation rights or alimony, is now a much stronger denouement to the continuing drama of Brexit.

5 get life term for kidnap of 6-year-old

GREATER NOIDA: A fast-track court sentenced five persons to life imprisonment for kidnapping a six-year-old boy and demanding Rs 50 lakh as ransom. The accused, who included two women, had kidnapped the nephew of a hospital owner from Surajpur in Greater Noida in May 2013, but were arrested two days later. The court of additional judge Ved Prakash Sharma heard the testimonies of the child and confessions of the accused before passing the order. The accused were identified as Sundar Chaudhary, Bacchu Singh, Mahendra, his wife Vimlesh and another woman, Hemlata. According to the order, Kartar Singh, a resident of Bhirondi

village and owner of a private hospital, had lodged a complaint on May 7, 2013, alleging that his nephew had gone missing from outside his house. The missing person's complaint was converted into an FIR after the family told the cops that they had got a call demanding Rs 50 lakh. A preliminary probe found the involvement of Sundar, who would allegedly frequent the house of Kartar Singh. "He was arrested on May 9, and later confessed to the crime.

Focus on last-mile connectivity to help improve ridership

NOIDA: The Noida Metro Rail Corporation (NMRC) has formed two teams to identify the areas that can be improved to increase its metro ridership. While Noida Metro's Aqua Line sees an average daily footfall of 17,000, it was expected to be higher by now. Due to several reasons, including lack of proper connectivity with Delhi Metro and a separate token and card system, the Noida Metro has still not seen the expected rise in footfall. The two teams will be holding meetings with residents' welfare associations (RWAs) and corporate groups to encourage metro usage and facilitate last mile options.

Remote sensing to help Noida identify illegal buildings

NOIDA: Considering large stretches of village areas which are illegal and overgrown with encroachment, the Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority (UP Rera) has taken the support of the Remote Sensing Application Centre (RSAC) for a site inspection of projects which overstep plans in a region between Lucknow and Barabanki. The knowledge from the exercise to map and detect plan-transgression is expected to be implemented in future to map and regulate property encroachment in cities like Noida, Greater Noida and Ghaziabad in future where rampant unauthorized real estate growth in villages or villages notified for acquisition has been a major problem for the administration. "We are at present in the process of implementing remote sensing technology-based mapping at a stretch of land in Barabanki region. At a later stage, such satellite imaging-based observation and record of land stretches and plan transgression will also be implemented in cities like Noida, Ghaziabad and Greater Noida where encroachment and illegal growth of housing are evident," member, UP Rera, Balwinder Kumar told TBC. According to UP Rera officers, one of the biggest challenges in regulating real estate in the Uttar Pradesh are the rural areas which are built without sanctioned plans.

Ghaziabad boy battles storms, scales Mt Everest

GHAZIABAD: High-altitude sickness had claimed the life of a mountaineer. Two others in his team from Russia and Bulgaria had decided to call off the expedition. But 21-year-old Sagar Kasana continued in the inclement weather. Forty-six days later — on May 22 — the final-year student of Noida College of Physical Education had unfurled the Tricolour on Mount Everest, the highest peak in the world. Sagar's father Ajab Singh Kasana, a resident of Loni in Ghaziabad, said his son reached Kathmandu on April 4 and started the expedition two days later. He and his team reached the first base camp on May 3, trekking via Lukla, Fekdeag, Nemche Bazaar, Tyagbo Che Monastery, Dingboche and Laboche, his father said. Other than Sagar, mountaineers Krick Wood from Australia, Alexander of Russia and Bulgarian Evan Tommo were in the team. They reached the third base camp on May 4, but had to wait for 18 days at the fourth camp as the weather was unfavourable. Mount Everest has been in news recently over "human traffic jams" along the route.

4 Noida MBBS students die in e-way crash near Baghpat

MEERUT: Four students of Greater Noida's Sharda University were killed and another was injured after the car they were travelling in rammed a stationary truck on Eastern Peripheral Expressway near Baghpat on Tuesday morning. Police said all five were third year MBBS students. The deceased are Ludhiana's Kant Dhingra, Karishma Dhingra of Faridabad, Rampur's Mohd Shoaib and Abhishek Soni of Rajasthan. The injured, Aanchal Rana, lives in Moradabad.

Footfall low, NMRC plans coaching centres at 6 stations

GREATER NOIDA: A fast-track court sentenced five persons to life imprisonment for kidnapping a six-year-old boy and demanding Rs 50 lakh as ransom. The accused, who included two women, had kidnapped the nephew of a hospital owner from Surajpur in Greater Noida in May 2013, but were arrested two days later. The court of additional judge Ved Prakash Sharma heard the testimonies of the child and confessions of the accused before passing the order. The accused were identified as Sundar Chaudhary, Bacchu Singh, Mahendra, his wife Vimlesh and another woman, Hemlata. According to the order, Kartar Singh, a resident of Bhirondi village and owner of a private hospital, had lodged a complaint on May 7, 2013, alleging that his nephew had gone missing from outside his house. The missing person's complaint was converted into an FIR after the family told the cops that they had got a call demanding Rs 50 lakh. A preliminary probe found the involvement of Sundar, who would allegedly frequent the house of Kartar Singh.

Private firm cheats 100 youths with government job ruse

NOIDA: The office of the SP (city) in Sector 6 on Monday registered a complaint filed by a group of around 40 youths, who alleged they had been duped of anywhere between Rs 2-8 lakh each, by a private firm, on the pretext of offering them jobs. However, no FIR had been lodged at the time of this report going to press. The company — India Rising Corporation Limited (IRCL) — which has its office in C-25, Sector 8, had employed youths from across north India from states like Delhi, Rajasthan, Haryana, Bihar and UP, claiming they had got grants from the Union ministry of micro, small and medium enterprises .

Duo cheated of Rs 2.3 lakh with job offers

GHAZIABAD: In two separate incidents, two youths were allegedly cheated of Rs 2 lakh and Rs 31,000 by fraudsters on the pretext of providing them jobs with the Airports Authority of India (AAI) and Axis Bank, respectively. Both the complainants had uploaded their resumes on online job portals and had been approached by the accused. They were made to pay the money in the name of processing fees and security deposits, among others. BCom graduate Sonu Kumar, a resident of Jatwara, said he had applied for the position of ground staff in AAI in January 2018 through a website after seeing an advertisement on the site. "After

a week, I received a job offer letter with the signature and stamp of a senior AAI official on my residential address, which stated that I had been selected for the post. It also stated that I would be given a monthly salary of Rs 32,600 and several perks, including a laptop, mobile phone and conveyance allowances. It stated that my training would start from March 4, 2018. I was asked to deposit Rs 25,500 in a bank account as security deposit," Sonu said. He added that the offer letter also mentioned that the money should be deposited in the account of the AAI managing director's secretary within two days, and no cheque or demand draft would be accepted. He was also warned that if he did not do so, his candidature would be rejected after two days. After that, Sonu received calls from several callers who claimed to be from the AAI for over one month. The callers made him deposit an additional Rs 1.75 lakh in several bank accounts on one pretext or the other. Realising that he had been duped, he approached police in March 2018.

Noida to kick off projects held due to model code of conduct

NOIDA: With the model code of conduct (MCC) technically over, projects that have been on hold for almost two months are set to take off. "Model code of conduct is technically over with the end of elections, but we can wait till May 30. All pending work will now resume which includes authority and district administration work," said BN Singh, district magistrate Gautam Buddha Nagar. In GB Nagar some of the projects which were held up include the Rs 55.28 crore, 780 metre underpass at one of the busiest intersection of sectors 71-72 and sectors 51-52.

Ex-GDA clerk booked for corruption

GHAZIABAD: A former GDA clerk was booked for corruption after an investigation by the vigilance department into his income between 2007 and 2012 revealed that he had spent Rs 76 lakh more than his known sources of income. Police said the accused, Sanjeev Nagrath, was originally from Delhi but had been living with his family in Kavi Nagar for the past several years. The action against Nagrath came on a complaint that the anti-corruption unit received in 2014. A probe revealed that his income between 2007 and 2012 was around Rs 1.22 crore, but he had spent Rs 1.98 crore, which is over 60% more than his earnings. GDA secretary Santosh Kumar said that a year before he had joined, Nagrath had been removed from the development agency. Sources said Nagrath was found to have stolen some important documents from the office, which led to his expulsion. Sanjay Pandey, SHO of Sihani Gate police station, said that an FIR had been lodged against Nagrath under sections 13.1A (criminal misconduct by public servant) and 13.2 (punishment for criminal misconduct by public servant) of the Prevention of Corruption Act. The FIR was lodged following a detailed investigation by the anti-corruption unit of Meerut.

5-year-old playing outside home drowns in drain

NOIDA: A five-year-old boy died after falling into an open drain in Sector 66's Mamura area in the early hours of Tuesday. Police said the kid was playing outside a jhuggi in which he lived with his parents, when he slipped into the drain. Three other kids were present at the spot. The child's body was found at least a kilometre away of the spot where he slipped in. Police had to deploy excavators and other equipment to recover the body. The deceased, identified as Deva , was originally from Klan village in Shahjahanpur.

Four cops booked for molesting couple

GHAZIABAD: Four policemen, including a police post in-charge, have been booked for allegedly molesting and thrashing a 41-year-old woman and her husband in Masuri. The complainant alleged that the policemen, in connivance with one of her relatives with whom she has been fighting a property dispute, not only tried to evict her from the property but also implicated her and her husband in a false case. The FIR was registered against sub-inspector H P Singh — who is the in-charge of Dasna police post — and four unidentified cops, as well as the complainant's brother-in-law, on May 20 under sections 147 (rioting), 323 (voluntarily causing hurt), 504 (intentional insult) and 354A (sexual harassment) of the IPC at Masuri police station. The complainant said her brother-in-law had been harassing her family over a plot of land on which they have been living for the past 20 years. She added that she had also filed a case in a Ghaziabad court over the dispute. On February 5, 2019, the relative, with his accomplices, allegedly put a lock on the house when the couple had gone out. "When we called police, sub-inspector H P Singh, along with other officers, reached the spot.

Haryana cop's son, friend held for Rs 3 crore Amex credit card fraud

NOIDA: Two graduates, including the son of a Haryana police sub-inspector, were arrested in Noida on Saturday evening for allegedly cheating financial service provider American Express of Rs 3 crore. The gang involving two brothers and a friend would get credit cards issued in Australia with fake documents and use them to shop in jewellery showrooms across NCR. They would then sell the jewellery to get cash. Police said Sunil and Sandeep Beniwal are sons of Surjeet Singh Beniwal, a CID sub-inspector posted in Hisar. It was Sunil (26), a graphic designer in Australia on a five-

year student visa, who would get the credit cards issued in that country after furnishing forged documents and send them to his brother Sandeep Beniwal (24) and his friend Sandeep Kumar (23) in India. The duo would go on a shopping spree — mostly in jewellery showrooms — and use the credit cards for transactions. American Express has alleged this caused them a loss of Rs 3 crore. Circle officer Kaustubh said Sunil would provide forged details to get the credit cards issued in Australia. The photographs would be his, but other details such as addresses and names would be different every time he applied for a card. "For instance, N Ohlayan would become Neeraj Ohlayan in another card," he said. SP (city) Sudha Singh said at least two more names have come up in the investigation. "We have to verify whether they knew about the fraud or were just carriers," she said. While Sandeep Beniwal is a BTech from a college in Mumbai, his friend Sandeep Kumar is a graduate from a Gurgaon institute. Police said a list of transactions had revealed that the duo shopped in Connaught Place in Delhi, Indirapuram in Ghaziabad and Sector 18 in Noida. While Sandeep Beniwal would do the shopping, his namesake would keep watch on guards and for CCTV cameras. For transactions of more than Rs 50,000, Sandeep Beniwal would provide fake Aadhaar or Pan cards as proof. The arrests followed a complaint by Ashish Madan, manager at American Express. Repeated calls to Madan for a comment on Sunday went unanswered. The duo were arrested from Sector 17/16 intersection.

Lack of travel options makes buses pick up passengers on e-way: Report

Noida: Lack of public transport in Noida to travel to faraway places and increasing commuters have led buses to illegally pick up passengers from near the Mahamaya flyover on the Noida expressway. This was mentioned by the transport department in its report highlighting what action it has taken against buses stopping on the expressway. The report says that between April 16 and 30, the department challaned over 165 buses, filed FIRs against 27 operators and detained nearly 35 drivers and other staff. The illegal parking of buses had been causing long snarls on the expressway. "While there is no

rail head in the city, the government bus service is CNG-based and does not cater to faraway places. This is one of the main reasons for ready availability of passengers for the illegally plying buses," the report mentions.It adds that since there is perennial shortage of long-distance state-run buses, private players fill the gap to cater to the ever increasing commuter base in Noida.

Fraud dupes woman in name of installing mobile tower, held

RAJKOT: Two gang rapes have been reported from Una of Gir-Somnath district and Bhavnagar on Friday. Though the crimes had been committed three and one months ago, respectively, the complaints in these connections were lodged only on Thursday, said police. Nine persons have been arrested in connection with the two crimes. A 35-year-old widow in Dron village of Una taluka alleged she was gang raped by four persons. In her complaint, the survivor has accused Ravi alias Nilesh Bambhania who had befriended her and had taken her to the outskirts of Dron village and raping her in February this year. "While Bambhania was raping the survivor, two other accused Sandeep Sakhat and Manu Chauhan shot a video of the act before they raped her. They also blackmailed her of circulating the video clip. Then the fourth accused, Akshargiri Bawaji, who was driving the survivor back home on his bike, raped her on the way," said D D Gohel, inspector with Una police station. Gohel further said that the survivor also accused one Yasin Baloch of helping the accused in the crime.

Three snatch cabs after booking rides, held

NOIDA: Lack of public transport in Noida to travel to faraway places and increasing commuters have led buses to illegally pick up passengers from near the Mahamaya flyover on the Noida expressway. This was mentioned by the transport department in its report highlighting what action it has taken against buses stopping on the expressway. The report says that between April 16 and 30, the department challaned over 165 buses, filed FIRs against 27 operators and detained nearly 35 drivers and other staff. The illegal parking of buses had been causing long snarls on the expressway. "While there is no rail head in the city, the government bus service is CNG-based and does not cater to faraway places. This is one of the main reasons for ready availability of passengers for the illegally plying buses," the report mentions. It adds that since there is perennial shortage of long-distance state-run buses, private players fill the gap to cater to the ever increasing commuter base in Noida. "We know this would be a hassle for thousands of passengers, but the stoppage was illegal and could not be allowed. Parking of buses added to congestion and made the high-speed corridor risky for other vehicles," said Himesh Tiwary, assistant regional transport officer. With buses not being allowed to park near the Mahamaya stoppage, passengers will now have to go to Vaishali in Ghaziabad or the ISBTs at Kashmere Gate and Anand Vihar in Delhi. Many operators have now shifted the stoppage to Kalindi Kunj. These buses take passengers to parts of eastern Uttar Pradesh, Bihar and Madhya Pradesh. Experts said authorised parking space for interstate buses could solve the problem. "Once the drivers were penalised and forced to move away from under the Mahamaya flyover, they started picking up passengers a little further on the expressway. Eventually, they will find another spot along the road. This is because there is growing demand and need for this transport option. The government should provide an alternative parking space that will remove congestion from the expressway," said Amit Bhatt, director of integrated transport for World Resources Institute India.

हेल्प लाईन नंबर

गाजियाबाद प्रशासन

डीएम – 2824416
आवास – 2820106
एडीएम (सिटी) – 2828411
एडीएम (प्रशासन) – 2827016
सिटी मजिस्ट्रेट – 2827365
आयकर विभाग– 2714144
पासपोर्ट कार्यालय– 2721779

पुलिस अधिकारी

एसएसपी –2820758,9643322900
पुलिस अधीक्षक नगर–2854015
पुलिसअधी. यातायात–2829520
सीओ प्रथम– 2733070
सीओ द्वितीय – 2791769
सीओ एलआईयू– 2700925
सीओ लोनी– 3125539

जीडीए

उपाध्यक्ष जीडीए – 2791114
जीडीए सचिव – 2790891

अस्पताल

सी.एम.ओ. – 2710754
सी.एम.एस. – 2730038
आपातकालीन – 2850124
कोलम्बिया एशिया –3989896
यशोदा अस्पताल–2750001–04
गणेश अस्पताल –4183900
संतोष अस्पताल –2741777
सर्वोदय अस्पताल –2701694
नरेन्द्र मोहन अस्पताल 2735253
जिला अस्पताल(एम्बुलेंस) 2730038
यशोदा अस्पताल (एम्बुलेंस) 2701695
पुष्पांजली क्रांसले हॉस्पिटल 4188000
पुष्पांजली मेडिकल सेन्टर 43075600

बीएसएनएल

आदेश कुमार (जीएम) 2755777

अग्निशमन विभाग

नगर कन्ट्रोल रूम – 2734906
कोतवाली – 2732099
जिला कन्ट्रोल रूम –2766898

पुलिस स्टेशन

एसएचओ इंदिरापुरम–संदीप कुमार सिंह– 9643322921
एसएचओ लिंक रोड– लक्ष्मी सिंह चौहान– 9643322924
एसएचओ–साहिबाबाद– जितेंद्र कुमार सिंह– 9643322923
एसएचओ खोड़ा– सतेंद्र प्रकाश– 9643322922
कोतवाली – 2732088
सिहानी गेट – 2791627
कविनगर – 2711843
विजयनगर – 2740797
इंदिरापुरम – 2902858
लोनी – 2600097
अग्निशमन विभाग –2732099 9818702101
रेलवे इन्कवायरी –131

नगर निगम

नगरायुक्त– 2790425,2713580

विद्युत विभाग

मुख्य अभियंता – 2821025

पूछताछ

रेलवे कस्टमर –2797840, 139
रिजर्वेशन – 8888
रोडवेज इन्कवायरी –2791102

प्रेस विज्ञप्ति, समाचार, विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें।
Phone No.: 0120-2850800, 2850297

Gzb man rapes and blackmails student for six years, held

GHAZIABAD: A 32-year-old man was arrested on Thursday for allegedly raping a 23-year-old Law student on several occasions in Ghaziabad's Masuri area. Police said the accused Ikraam, a resident of Masuri, also threatened the woman of making her obscene video public if she did not marry him. The woman belongs to Delhi and is a fifth year Law student in Royal college in Masuri. "My aunt lives in the same neighbourhood as Ikraam. I knew his family and used to meet them. When I was 17-years-old, Ikraam called me to his house and gave me a drink laced with sedatives. He, thereafter, raped me. He made an obscene video of me at that time and has since raped me on several occasions by threatening me to make the video public. He now has started to pressurise me to marry him even though he is already married with four kids," as the woman said in the complaint. "On Tuesday morning, the accused reached the woman's college and tried to misbehave with her.

Stalker booked for threatening Ghaziabad woman

GHAZIABAD: A 25-year-old woman has filed a complaint against a Delhi resident accusing him of threatening her with acid attack after her family fixed her marriage with somebody else. According to the woman, the 26-year-old man has also attempted to kidnap her and even threatened to kill her family. The accused has been identified as Preet, a resident of Ghazipur in Delhi. "Both the woman and the accused knew each other as they studied in college together," said Sanjay Pandey, the SHO of Sihani Gate police station.

NTPC executive accused of raping 11-year-old, held

NOIDA: A 45-year-old NTPC official has been arrested for allegedly raping an 11-year-old girl for over a year on the pretext of helping her with studies at his home. The girl, a student of a prominent Noida school, confided in one of her teachers, who informed her parents. An FIR was lodged this Sunday. The accused, Akhil Gupta, who has a college-going daughter and a son who studies in Class VIII, was arrested on Tuesday morning. Circle officer Piyush Singh said the accused had been booked under IPC Section 376 (rape) and sections 3 and 4 of the POCSO Act. Gupta's family shared close ties with the girl's parents and the 11-year-old would often visit the NTPC official's house to get help in her studies. Both Gupta and the girl's family live in the same housing society. Police said the accused would make the girl and his son sit in different rooms when she went to his house and instructed his wife not to disturb him while he "taught" the children. "The director of the school asked us to come for a meeting. We took along two close friends from the housing society.

Five booked for thrashing woman

NOIDA: Five persons have been booked for allegedly beating up a six-month pregnant woman in Kasna last week and threatening her to withdraw a complaint of rape. The five accused include Vinit Rajbhushan and his nephew Ankit, residents of Dadha village, whom the woman had accused of gang rape and making her pregnant. An FIR was lodged against Vinit and Ankit following a court order in December last year. The woman alleged that around 10.30pm on May 21, when she was returning home on her scooter, the five accused allegedly hit her with their car and beat her up with sticks and rods.

Jewar airport plan to get fresh push

GREATER NOIDA: With the Lok Sabha elections over, the nod from the state government on the Jewar concessionaire bid document is likely to come by next month. Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) sources said the government is likely to give its approval following a recommendation from the project monitoring and implementation committee. After the nod, the process of issuing global tenders for the construction of the airport will begin. The bid document received the final approval from the Union ministry of civil

aviation in February this year. Expected to be ready by 2023, the Jewar airport aims to take load off Delhi's Indira Gandhi International airport. "We will initiate global tendering for the airport project once the state government approves the bid document," said YEIDA chief Arun Vir Singh. Singh maintained that the bid document was "finalised as per Government of India in February 2019". He added, "All media speculations regarding number of domestic/international terminals as well as number of footfall per year at the proposed airport is totally wrong as it can't be determined as of today." YEIDA is waiting for the Delhi Metro Rail Corporation's (DMRC) revised plans for the Airport Express line as well as the commercial connectivity line to Jewar. "We had our second meeting with DMRC on May 10, in which we have asked for a new chapter on a separate dedicated airport line for Jewar, which should run parallel to the current proposed 35.

Friendly 'doctor' who stole vehicles arrested in Greater Noida

NOIDA: A man claiming to be a homeopathic doctor was among two people arrested in Greater Noida on Wednesday on charges of lifting vehicles of people after befriending them, according to police. Accused Kapil Verma has been involved in at least three such cases where he has tricked people into lending their cars to him for some time and within days, the vehicles went missing, a senior police officer said. "He would get in touch with people and befriend them. Eventually he would ask for their vehicle for a day or for some time on some or the other pretext.

Noida project first to be deregistered by UP-Rera

NOIDA: Unnati Fortune's Aranya, located in Noida's Sector 119, has become the first housing project to be de-registered by the Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority (UP-Rera), a move that is likely to affect some 2,000 buyers who have been waiting for a period ranging between three and five years for their homes. While Rera benches have taken several steps against defaulting builders across the country, this is perhaps the first time that a housing project has been de-registered in India. UP-Rera officials said this was the first such move under the new real estate law. The regulatory authority de-registered Aranya phases 3, 4 and 5 under Section 7 of the Rera Act after the developer failed to come up with a satisfactory response to the notices before the UP bench. The project, which began in 2007, is valued over Rs 1,500 crore. Officials said notices were served to the developer after UP-Rera detected severe financial irregularities and funds diversion by Unnati Fortune. "The de-registration order was served based upon the information collected, inspections made of the site, complaints registered with UP-Rera and non-compliance of the provisions of the Rera Act," said chairman Rajive Kumar. "While they were already given strict warnings almost three months ago, this decision was taken after we gave them ample amount of time to respond after repeated notices were issued to them. This step should be seen as a warning to other builders as well," he added. Commenting on the next step, UP-Rera secretary Abrar Ahmed said after the de-registration, "There are several options before the Authority, besides giving the first right of completion to buyers. If the buyers themselves are in a position to complete the housing project by pulling their finances together, we will develop a mechanism to supervise that."

In Noida, cops hand over seized liquor to smugglers, booked

GREATER NOIDA: Two sub-inspectors deployed at Kasna police station were booked on Thursday for allegedly colluding with with liquor smugglers for monetary benefits. The accused policemen allegedly handed over a seized consignment of 2,700 bottles of illegal liquor to two smugglers. One of the sub-inspectors was praised some days ago for helping a Chinese tourist who had lost his way in Greater Noida. The matter was revealed on Wednesday after police raided a warehouse of illegal liquor in Sector Chi 4 from where they seized 2,700 English and Indian liquor bottles which were meant to be sold in Haryana. While one man was nabbed from the warehouse, his accomplice managed to escape. During questioning, the arrested man, Sanjay Bhati, revealed that two sub-inspectors, Vikas Kumar and Komal Kuntal, handed over the liquor to them for 'smuggling'. "The two sub-inspectors were reprimanded over the allegations. The main accused Komal Kuntal has admitted that he had colluded with Bhati and his accomplice Yogi for financial gains.

क्रॉसिंग रिपब्लिक में फायर स्टेशन के लिए मिली जमीन

गाजियाबाद : क्रासिंग रिपब्लिक में आग लगने के दौरान दमकल विभाग को होने वाली दिक्कतों का जल्द समाधान होने वाला है। काफी समय से क्रॉसिंग रिपब्लिक में तलाशी जा रही फायर स्टेशन के लिए जमीन मिल गई है। डीएम के प्रयास से ढाई हजार वर्ग मीटर जमीन मिली है। सीएफओ का कहना है कि जीडीए की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। वहीं लोनी में अभी फायर स्टेशन का प्रस्ताव शासन में लंबित है। इसके लिए लोनी विधायक ने शासन को पत्र लिखा है। क्रॉसिंग रिपब्लिक में हाइराइज बिल्डिंग होने के बाद भी फायर स्टेशन नहीं हैं। यहां पर हजारों लोग इन सोसायटियों में रहते हैं। आग लगने की स्थिति में यहां कोतवाली और वैशाली से गाड़ी भेजी जाती है। इसके लिए दमकल विभाग काफी समय से जमीन की मांग कर रहा था। काफी समय से जमीन चिंहित करने का काम चल रहा था लेकिन जमीन नहीं मिल पा रही थी। सीएफओ सुनील सिंह ने बताया कि डीएम रितु माहेश्वरी के अथक प्रयासों से पुलिस चौकी के पास करीब ढाई हजार वर्ग मीटर जमीन मिल गई है। जीडीए की बोर्ड बैठक में फायर स्टेशन बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। शासन से अनुमति मिलते ही काम शुरू कराया जाएगा।

लोनी का प्रस्ताव शासन में लंबित

लोनी में करीब 16 लाख की आबादी है और यहां पर काफी संख्या में उद्योग भी हैं। बावजूद इसके यहां पर दमकल विभाग की ओर से फायर स्टेशन नहीं है। लोनी में विभाग की ओर से ट्रॉनिका सिटी थाने में एक दमकल की गाड़ी स्थाई रूप से तैनात कर दी गई है। ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र में जमीन मिली है। प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। शासन से मंजूरी अटकी हुई है। इस संबंध में विधायक लोनी नंद किशोर गुर्जर का कहना है कि 6 मार्च को शासन को पत्र लिखकर जल्द अनुमति की मांग की गई है।

जिला एमएमजी में डिजिटल एक्स–रे मशीन खराब

गाजियाबाद : जिला एमएमजी अस्पताल में अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अस्पताल में डिजिटल एक्स–रे मशीन पिछले एक महीने से खराब पड़ी है जबकि हार्मोनल जांच भी अस्पताल में नहीं हो पा रही हैं। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि इसके लिए जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यालय को भी मशीनों की बाबत रिमाइंडर भेजा गया है। डिजिटल एक्स–रे मशीन के लिए बेंगलुरु से उपकरण आने हैं। उपकरण आते ही मशीन सुचारू रूप से कार्य करेगी। डिजिटल एक्स–रे नहीं होने के चलते अस्पताल में आने वाले मरीजों के नार्मल एक्स–रे केवल एक ही मशीन से किए जा रहे हैं। इससे मरीजों का इंतजार बढ़ जाता है और इमरजेंसी में होने वाले एक्स–रे में भी देर हो जाती है। जिला एमएमजी अस्पताल में रोजाना करीब 250 लोगों का एक्स–रे किया जाता है। इनमें छाती, गर्दन, कमर के अलावा हाथ और पैरों के भी एक्स–रे किए जाते हैं। जिला एमएमजी अस्पताल में हारमोनल जांच के लिए लगभग डेढ़ करोड़ रुपए की मशीन करीब चार महीने पहले मंगाई गई थी।

330 में से 28 समूहों को ही बैंकों से लोन हो सका स्वीकृत

गाजियाबाद : स्वयं सहायता समूहों की राह में पैसों की कमी रोड़ा बनी हुई है। ग्राम विकास विभाग स्वयं सहायता समूहों को तमाम रोजगारपरक कार्यक्रम दे चुका है लेकिन स्वरोजगार के लिए सबसे ज्यादा जरुरी धन की कमी के चलते स्वयं सहायता समूह ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। हालत यह है कि अब तक सिर्फ 28 समूहों को ही बैंकों से लोन स्वीकृति मिली है। जबकि 300 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह जिले में काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में 10–10 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए गए थे। जिले में करीब 300 स्वयं सहायता समूह बनाए गए। इन समूहों के सदस्यों में स्वावलंबन की भावना बढ़ाने के लिए इन्हें विभिन्न रोजगारपरक कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देकर इन्हें लघु उद्योगों के क्षेत्र में लगाना था मगर धन की कमी इन समूहों के काम में बाधा बन रही हैं। ग्राम विकास विभाग ने 49 समूहों के लोन आवेदन किए थे। जिनमें से अभी तक 28 को ही स्वीकृति मिली है। जिसकी वजह से समूह ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। जिला विकास अधिकारी भालचंद्र त्रिपाठी ने बताया कि बैंकों को पत्र लिखा गया है।

योजनाओं में अधिकारी दिखाएं रुचि : प्रमुख सचिव

गाजियाबाद : जिले की प्रभारी अधिकारी एवं प्रमुख सचिव आबकारी व पर्यावरण एवं वन कल्पना अवस्थी ने मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं में अधिकारी रुचि दिखाएं और रुचि के साथ ही काम करें। इसके साथ ही शासन द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों को गुणवत्ता व समयबद्धता के साथ करते हुए लोगों तक उनका लाभ पहुंचाया जाए व जानकारी मुहैया कराई जाए। बैठक में कल्पना अवस्थी ने निर्देश दिए कि चुनाव के बाद इस वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के अनुरूप सभी विभाग टारगेट प्राप्त कर उन्हें पूरा करने में जुट जाएं। उन्होंने कहा कि नगर निगम व नगर निकाय पर्यावरण संरक्षण के लिए एनजीटी द्वारा बनाई गई कमेटी से जारी निर्धारित नियमावलियों के अनुरूप कार्य कराएं। प्रमुख सचिव ने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई–वेस्ट आदि का निवारण इस तरह से कराएं इसके दुष्परिणाम न हों। नगर निगम इनका योजनाबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित करे। प्रमुख सचिव ने नगरायुक्त को निर्देश दिए कि प्रदूषित जल को किसी भी सूरत में नदी व नहरों में न जाने दिया जाए। इसके प्रबंधन के लिए वहां जालियां लगवाएं, जिससे कचरा नदियों में न जा पाए।

अब पसीना, खून और लार से पता चलेगा कि तनाव है या नहीं

नई दिल्ली : वैज्ञानिकों ने एक नयी जांच विकसित की है जो पसीना, खून, मूत्र या लार के जरिए सामान्य तनाव को आसानी से माप सकती है। तनाव को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसका असर हृदय रोग से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक पर पड़ता है। अमेरिका के सिनसिनाटी यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों को उम्मीद है कि नयी जांच के जरिए रोगी घर पर ही इस उपकरण का इस्तेमाल कर सकेंगे। दरअसल, वैज्ञानिकों ने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो खून, पसीना, मूत्र या लार में मौजूद तनाव को हार्मोन की पैराबैंगनी किरणों के जरिए माप करेगा।

BUREAU OFFICE
PRATEEK BHARGAVA
Bureau Chief
5, Ashok Vihar, 3rd Floor,
GMS Road, Nr. Ballupur
Chowk, Dehradun.
Mobile: +91 8130640011
Email: prateekb@tbcgzb.com
www.tbcgzb.com
Contact for Press Release
and Advertisements

BUREAU OFFICE
VIKRAM KUMAR
Bureau Chief
12/516, Friends Co-operative
Society Vasundhra,
Ghaziabad (UP)
Mobile: +91 8130640077
Email: vikram@tbcgzb.com
www.tbcgzb.com
Contact for Press Release
and Advertisements

10 करोड़ से अधिक के ऋण वितरित होंगे

गाजियाबाद : ओडीओपी (एक जनपद एक उत्पाद) योजना के लिए शासन ने इस बार जनपद का लक्ष्य बढ़ाकर दोगुना कर दिया है, जिसके तहत गुड्स इंडस्ट्रीज, सर्विस और व्यापार के लिए 50 लोगों को सब्सिडी वाले 10 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरित किए जाएंगे। गत वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत आठ लोगों को करीब सवा चार करोड़ के ऋण वितरित हुए थे। प्रदेश सरकार ने जिला उद्यम एवं प्रोत्साहन उद्योग केंद्र को मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए ओडीओपी योजना के तहत लक्ष्य निर्धारित कर भेजा गया है, जिसमें इस बार गत वित्तीय वर्ष के मुकाबले लक्ष्य दोगुना किया गया है।

यूपी में कैसे हुई सपा की हार, अखिलेश यादव ऐसे कर रहे हैं पड़ताल

लखनउ : लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारण तलाश रहे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को भी हारे हुए प्रत्याशियों, उनके पोलिंग एजेंटों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश ने पिछले कई दिनों से जारी सिलसिले में आज भी विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी रहे नेताओं और उनके पोलिंग एजेंटों एवं कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर उनका पक्ष जाना। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे लोकसभा चुनाव में मिली पराजय से मायूस होने के बजाय जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत बनायें और वर्ष 2022 में होने वाले प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। इस सवाल पर कि लोकसभा चुनाव में मिली पराजय के बाद सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव से अखिलेश की कोई बातचीत हुई है, चौधरी ने कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। बसपा के साथ गठबंधन को लेकर हुए नफे–नुकसान के बारे में भी सपा में कोई चर्चा होने के बारे में पूछे जाने पर चौधरी ने इससे भी इनकार किया। गौरतलब है कि बसपा और रालोद से गठबंधन करके लोकसभा चुनाव में उतरी सपा को खासा नुकसान हुआ है।

Printed and Published by Dheeraj Kumar Bhargav at B.F.L Inrotech Ltd, C-9, Sector-3 Noida, Distt. Gautam Budh Nagar and Published at 282, Sarai Nazar Ali, behind MMG Hospital Ghaziabad (U.P.) 201 001. Editor: Dheeraj Kumar, Resident Editor : Manisha Bhargava** Email: editor@tbam.co.in **(RNI. No) : UPBIL / 2009 / 28691 Postal Registration No. UP/GBD-80/2016- 18.** Advertisement : Ph. No. : 0120-2850800, 2850297, Fax : 0120-4561000 at 67, 1st Floor, Richpal Puri, Hapur Road, Ghaziabad (U.P.)** Responsible for selection of News under the PRB Act. Reproduction in any manner, electronic or otherwise in whole or in post without prior written permission is prohibited.